आज़ादी का अमृत महोत्सव

समावेशी राह पर ग्रामीण भारत

–अरविंद कुमार मिश्रा

देश के 130 करोड़ नागरिक आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह अवसर एक ओर जहां स्वतंत्रता के 75 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा से प्रेरणा लेने का है, वहीं आज हमारे द्वारा लिए गए संकल्पों पर समावेशी भारत की भव्य इमारत खड़ी होगी। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर और वैश्विक भूमिकाओं में अग्रणी उपस्थिति दर्ज कराने वाला हो। आज़ादी का अमृत महोत्सव अतीत और भविष्य के बीच समन्वय का सेतु विकसित करने का आह्वान है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा, 75 वर्षों की उपलब्धियां, नए संकल्प, कार्यक्रम और विचार समाहित हैं। गांव आज़ादी के सौ वर्ष (भारत@2047) की विकास यात्रा का प्रमुख केंद्र होंगे। इसकी वजह ग्रामीण भारत का जनसांख्यिकी और भौगोलिक आकार है।

2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में 68.84 प्रतिशत आबादी रह रही है। आर्थिक सर्वे 2020–21 के अनुसार कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 20 प्रतिशत है। गांव की तरक्की के सामाजिक और आर्थिक प्रतिमान जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोज़गार, बिजली, पानी, स्वच्छता और सड़क में विगत कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। गांव अब पलायन व बेरोज़गारी नहीं बल्कि नवाचार और खुशहाली के प्रतीक हैं। ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता के पीछे आधुनिक ग्रामीण संपर्क अधोसंरचना का बड़ा योगदान है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ज़रिए 7 लाख किमी. से ज़्यादा पक्की सड़कों व 6 हज़ार पुलों के निर्माण ने ग्रामीण विकास को गति दी है। इससे एक ओर जहां किसानों की बाज़ार तक पहुंच आसान हुई है, वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सुगम हुई है। रूस–यूक्रेन युद्ध के समय जब कई देशों में खाद्य संकट मंडराया, उस वक्त भारत खाद्य पदार्थों की आपूर्ति का केंद्र बनकर उभरा है। वर्ष 2021–22 में कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण भारत की निर्यात आमदनी 50 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गई।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते ग्रामीण भारत की इस यात्रा में भारतीय रेल परियोजनाओं के विस्तार का अहम योगदान है। किसान रेल जैसी सुविधाएं दूरस्थ इलाकों में स्थित किसानों को महानगरों तक अपने उत्पाद बेचने का अवसर प्रदान कर रही हैं। मार्च 2022 तक किसान रेल के जरिए 153 रूट पर छह लाख टन कृषि उपज का परिवहन किया जा चुका है। ग्रामीण संपर्क में

ग्रामीण संपर्क में उड्डयन सेवाओं में निहित संभावनाएं लंबे समय तक उपेक्षित रही हैं। उत्तर–पूर्व और पहाड़ी राज्यों के कृषि उत्पादों को हवाई परिवहन उपलब्ध कराने के लिए किसान उड़ान योजना शुरू की गई है। गैर–परम्परागत क्षेत्रों से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 'हैप्पी बनाना' ट्रेन ने ग्रामीण संपर्क को नई ऊंचाई दी है। किसान कनेक्ट पोर्टल जैसी डिजिटल पहल की बदौलत नए कृषि निर्यात क्षेत्र तैयार हो रहे हैं। वाराणसी (सब्जियां, आम), अनंतपुर (केला), नागपुर (संतरा), लखनऊ (आम), थेनी (केला), सोलापुर (अनार), कृष्णा तथा चित्तूर (आम) जैसे क्लस्टर इसके आदर्श उदाहरण हैं।

परिवहन ढांचे के साथ डिजिटल क्रांति के मेल ने ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य और ई–कॉमर्स की गांव में मौजूदगी को बढ़ाया है। आज राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई–नाम) के द्वारा कृषि उत्पादों के लिए बेहतर कारोबारी अवसर गढ़े जा रहे हैं। 14 अप्रैल, 2016 को उद्घाटित इस अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल ने मंडी संचालन को पारदर्शी बनाया है।

डिजिटल संपर्क से गांव में तरक्की की बयार

गांव तक बुनियादी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में डिजिटल सेवाओं की अहम भूमिका है। डिजिटल सेवाएं अब गांव और शहर के बीच के अंतर को कम कर रही हैं। देश में लगभग 1,17,440 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का संचालन किया जा चुका है। टेलीमेडिसिन सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए 3.74 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को ई–संजीवनी एप्लिकेशन से जोड़ा गया है। गांव में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति मिलने से स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय शासन तंत्र, बैंकिंग सेवाओं का दायरा बढ़ा है। डिजिटल पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी और गांव की चौपाल तक डिलीवरी बॉय की दस्तक ग्रामीण भारत में डिजिटल पदचिन्हों के बढ़ने का परिणाम है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वयंसहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई–मार्केट से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। देश की पंचायतों के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को केंद्र सरकार प्रोत्साहित कर रही है। 15वें वित्त आयोग से राष्ट्रीय ग्राम स्वरोज़गार अभियान के लिए 5,911 करोड़ रुपये आरक्षित किए गए हैं। पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर एक ही छत के नीचे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करते हैं। 2.30 लाख ग्राम पंचायतें ई–ग्राम स्वराज एप्लीकेशन को अकाउंटिंग, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। केंद्र सरकार ने स्वयंसहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को ई–कॉमर्स कंपनियों के साथ संबद्ध किया है। फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन जैसे प्रयासों से स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाज़ार मिल रहा है।

स्वामित्व योजना

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स तकनीक ने ग्रामीण संपर्क को नई ऊंचाई दी है। भूमि के मालिकाना हक प्रदान करने की डिजिटल व्यवस्था के तहत स्वामित्व योजना के अंतर्गत 20 अप्रैल, 2022 तक 1.30 लाख गांवों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है। यह योजना पंचायती राज दिवस के अवसर पर 20 अप्रैल, 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत सम्पत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है।

ग्रामीण भारत के विकास को 'गतिशक्ति'

ग्रामीण भारत की तरक्की को रफ्तार देने के साथ उसे टिकाऊ बनाने में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की सबसे अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति महज एक मास्टर प्लान नहीं बल्कि नीतियों और उन पर टिकी परियोजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और टिकाऊ बनाने का समन्वित प्रयास है। इसके अंतर्गत बुनियादी अधोसंरचना क्षेत्र से जुड़ी 100 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अंतर्संबंधित किया गया है। यह परियोजनाएं 16 मंत्रालयों से संबंधित हैं। सभी परियोजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन को डिजिटल मंच से आगे बढ़ाया जाता है। इसका सीधा लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्जवला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारतनेट, दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वामित्व योजना जैसे कार्यक्रमों को मिलेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू–सूचना विज्ञान संस्थान ने गति शक्ति योजना की निगरानी के लिए प्लेटफार्म विकसित किया है। यह योजना भू–स्थानिक मैपिंग को आगे बढ़ाती है। उदाहरण के लिए पीएम गतिशक्ति योजना से शहर और गांव के मध्य संपर्क को मज़बूत करने वाली डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) जैसी परियोजनाओं को तय समयावधि में पूरा करने में सहायता मिलेगी। डीएफसी के ज़रिए मालगाड़ियों के लिए अलग रेलवे ट्रैक बनने से वस्तुओं की ढुलाई पर आने वाली लागत में कमी होगी। इससे फ्रेट कॉरिडोर के स्टेशनों के आसपास सरकारी और निजी क्षेत्र के वेयरहाउस बनेंगे, जिससे कृषि उत्पादों की बर्बादी कम होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जहां से गुज़र रहा है, उन ग्रामीण कस्बों व तहसीलों के आसपास नए बाज़ार विकसित हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने गति शक्ति मिशन के तहत 11 औद्योगिक कॉरिडोर

आज़ादी के अमृत महोत्सव के पांच आयाम

- स्वतंत्रता संग्राम
- उपलब्धियां
- संकल्प–समाधान
- कार्यक्रम
- विचार दृष्टि (विज़न@75)

'स्वामित्व योजना' के तहत ड्रोन तकनीक से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पार्सलों के सर्वेक्षण और मानचित्रण का कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण चार वर्षों (2020–2024) की अवधि में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

और 2 रक्षा कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। इसके तहत हर गांव को 4जी नेटवर्क कवरेज के दायरे में लाना, नेशनल हाईवे नेटवर्क का 2 लाख किलोमीटर तक विस्तार, 220 नए एयरपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और वॉटर एयरोड्रम बनाने का लक्ष्य है।

सरकार 17,000 किलोमीटर लंबा नई गैस पाइपलाइन का नेटवर्क तैयार कर रही है, इससे गांवों तक सीएनजी और पीएनजी की पहुंच आसान होगी। पीएम गति शक्ति के समानांतर केंद्र सरकार वर्तमान में एक लाख करोड़ रुपये भंडारण व सिंचाई का रकबा बढ़ाने में खर्च कर रही है। इसका उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ग्रामीण बाज़ार विकसित करना है। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कच्चा माल आसानी से मिलेगा। ग्रामीण संपर्क को मज़बूत करने में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना की विशेष भूमिका रहेगी। अगस्त 2020 में शुरू 102 लाख करोड़ की एनआईपी परियोजना का उद्देश्य 2020–2025 की अवधि में विश्व–स्तरीय आधारभूत ढ़ांचा तैयार करना है। इसी के समानांतर सरकार द्वारा शुरू की गई 6 लाख करोड़ रुपये की नेशनल मोनेटाइज़ेशन पाइपलाइन का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए निवेश जुटाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पंचायत स्तर के लिए आपदा प्रबंधन की रूपरेखा तैयार की गई है। बाढ़, सूखा व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधक दल खड़ा करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। देश को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने व लोगों के जीवन–स्तर में गुणात्मक परिवर्तन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसहायता समूहों और स्टार्टअप की भूमिका बढ़ानी होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सामाजिक समर्थन, कम भ्रष्टाचार, सामुदायिक उदारता और जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता ऐसे कारक हैं, जिससे हमारे गांव जीवन की उत्कृष्टता के केंद्र बन रहे हैं।

ईज़ ऑफ लिविंग के नए आयाम गढ़ते गांव

आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध नागरिकों के आत्मविश्वास से है। आवास, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा वह बुनियादी सुविधाएं हैं जो लोगों के जीवन–स्तर में बदलाव लाने के साथ उनमें भरोसा पैदा करती हैं। देश ने विगत छह वर्षों में ग्रामीण जनजीवन को गुणवत्ता देने से जुड़ी अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। आज़ादी के बाद लोक कल्याणकारी राज्य की जिस अवधारणा को दार्शनिक नज़रिए तक ही सीमित रखा गया, उसे भारत के गांवों में व्यावहारिक धरातल पर सच होते देखा जा सकता है। देश में मार्च 2024 तक हर व्यक्ति के अपने 'घर' का 'स्वप्न' साकार हो जाने की उम्मीद है।

अप्रैल 2022 तक ग्रामीण इलाकों में 2.52 करोड़ आवास बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण में 1.95 करोड़ मकानों के निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है। किसी भी सार्वजनिक पहल को टिकाऊ बनाने के लिए उपेक्षित तबके का आर्थिक व सामाजिक सशक्तीकरण ज़रूरी है। प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों के अनुसार आवास अभाव मानदंड पर किया जाता है। लाभार्थियों की सूची ग्रामसभा द्वारा मान्य की जाती है। पीएम आवास योजना महिला

आत्मनिर्भर गांव के पांच स्तंभ

- ग्रामीण अर्थतंत्र
- ग्रामीण अवसंरचना
- तकनीक–आधारित सेवाएं व सुशासन
- ग्रामीण भारत की जनसांख्यिकी व भौगोलिक क्षमता
- मांग और आपूर्ति के केंद्र

पल्ली व ओडांथुरई पंचायत : आत्मनिर्भर गांव के पदचिन्ह

जम्मू–कश्मीर के सांबा का पल्ली गांव भविष्य के गांव का आदर्श उदाहरण है। यह कार्बन मुक्त सौर पंचायत है। इस पंचायत में आपको पक्की सड़कों से लेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा, उन्नत पंचायत घर, पुनर्निर्मित सरकारी हाईस्कूल भवन, जल संरचनाएं, खेल मैदान, एटीएम सब कुछ मिलेगा। केंद्र सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत इस आदर्श पंचायत में 340 घरों को स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने के लिए 500 केवी सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। गांव के लगभग हर घर में सौर चूल्हे भी हैं। भूमि अभिलेख सूचना प्रणाली आपकी ज़मीन आपकी निगरानी पोर्टल (landrecord jk.gov.in) के ज़रिए कोई भी एक क्लिक पर अपना राजस्व रिकॉर्ड देख सकता है। ई–ऑफिस से तकनीक आधारित जनसेवा वितरण प्रणाली व्यवस्था के लाभ स्थानीय लोगों को मिलते हैं। पल्ली से काफी समय पहले तमिलनाडु के ओडांथुरई गांव में आत्मनिर्भर गांव के पदचिन्हों को दुनिया देख चुकी है। पंचायती राज संस्थाओं के जरिए गांव को कैसे आधुनिक शक्ल दी जा सकती है, ओडांथुरई इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। गांव में सभी पक्के घर, हर घर में नल से जल सप्लाई, सौर ऊर्जा से जगमग रोशनी, पवन चक्कियों से बिजली उत्पादन और रोज़गार सुरक्षा इसकी पहचान है। यह पंचायत अतिरिक्त बिजली उत्पादन से 19 लाख से अधिक सालाना की कमाई कर रही है। देश के लोकतांत्रिक सशक्तीकरण तथा ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की अवधि 2026 तक बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए लगभग छह हज़ार करोड़ के वित्तीय आवंटन को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। विकास की यात्रा में देश का कोई भी ज़िला पीछे न छूटे, इसे ध्यान में रखते हुए 2018 में आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (एडीपी) शुरू किया गया। आकांक्षी ज़िलों के रूपांतरण कार्यक्रम में 28 राज्यों के 115 ज़िले शामिल हैं। 1. स्वास्थ्य और पोषण, 2. शिक्षा, 3. कृषि और जल संसाधन, 4. वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, 5. सड़कों सहित मूल आधारभूत संरचना (आवास, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, घरेलू शौचालय, इंटरनेट कनेक्शन और साझा सेवा केंद्रों) पर बल दिया गया है।

सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है। इसके तहत महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त सदस्य के नाम पर मकान का स्वामित्व प्रदान किया जाता है। 24 जनवरी, 2022 तक 66.90 प्रतिशत घर या तो महिला लाभार्थियों या पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर हैं। गृह निर्माण के विभिन्न चरणों की निगरानी के लिए इसे जियो टैगिंग से जोड़ा गया है। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। साथ ही, घर में शौचालय, पानी और बिजली की सुविधा से ईज़ ऑफ लीविंग का मंत्र चरितार्थ हो रहा है।

गांवों में विद्युतीकरण के शत–प्रतिशत लक्ष्य को तय समय से पूर्व हासिल किया गया है। सौभाग्य योजना के तहत 3 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया गया है। स्वच्छ ईंधन व्यक्ति और पर्यावरण दोनों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के जरिए 8 करोड़ गैस कनेक्शन वितरित किए गए। इस योजना के सबसे बड़े हितग्राही गरीब, दलित, वंचित और आदिवासी परिवार हैं। देश के हर गांव में 2024 तक स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन–हर घर जल के तहत 9 करोड़ 47 लाख 74 हज़ार 361* घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 के तथ्य ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य परितंत्र की मज़बूती के लिए उठाए गए कदमों की पुष्टि करते हैं। एनएफएचएस शुरू होने के बाद पहली बार देश में महिलाओं का अनुपात पुरुषों से अधिक हुआ है। देश में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। वर्ष 2015–16 में प्रति 1000 पुरुषों पर 991 महिलाएं थीं। इसका श्रेय महिला सशक्तीकरण के लिए वित्तीय समावेशन और लैंगिक पूर्वाग्रह तथा असमानताओं से निपटने के उपायों को जाता है। बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक अभियानों से छात्राओं के पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी आई है। लैंगिक समानता के प्रयासों के क्रम में लड़कियों के विवाह की उम्र को 18 से 21 किया जाना एक महत्वपूर्ण फैसला है।

*जल जीवन मिशन कवरेज (28.04.22)–49.06 प्रतिशत

आज़ादी का अमृत महोत्सव : ग्रामीण विकास के 9 लक्ष्य*

- गरीबी से मुक्ति
- उन्नत आजीविका
- स्वास्थ्य
- बाल हितैशी
- जल संपन्नता
- स्वच्छता एवं हरियाली
- आत्मनिर्भर अधोसंरचना
- सुशासन
- महिला सशक्तीकरण

*ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित

लोगों का जीवन–स्तर व प्राथमिकताएं जैसे–जैसे बदल रही हैं, उसे ध्यान में रखते हुए अब लोगों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का आवरण देना होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि कार्यक्रमों से केंद्र सरकार ने अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा दी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे में कृषि आधारित आजीविका व उद्यमशीलता को हरित रोज़गार उपक्रमों से जोड़ना होगा। इस दिशा में कौशल विकास पर ज़ोर देने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहायक होगी।

गांव की आत्मनिर्भरता के पांच स्तंभ

आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में गांव की आधारभूत संरचना को अगले दशकों की ज़रूरत के अनुसार गढ़ने का संकल्प देश के 130 करोड़ नागरिकों द्वारा प्रायोजित है। 'आत्मनिर्भर' भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पांच स्तंभों पर खड़ी होगी। पहला, ग्रामीण अर्थतंत्र जो गांव के विकास में संख्यात्मक नहीं गुणात्मक परिवर्तन लाने वाला हो। आज पूरी दुनिया जिस तरह अर्थ केंद्रित विकास की ओर बढ़ रही है, ऐसे समय में गांव प्रकृति केंद्रित नैसर्गिक विकास की ओर उन्मुख नज़र आएं। दूसरा, ग्रामीण अवसंरचना जिसमें ग्रामीण संपर्क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, अक्षय ऊर्जा, सिंचाई जैसी आधारभूत संरचनाएं आधुनिक भारत को पहचान देने वाली बनें। तीसरा, ग्रामीण विकास से जुड़े शासन तंत्र को तकनीक उन्मुख बनाना होगा, अर्थात् सेवाओं व व्यवस्था की निगरानी के लिए ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाए जो तकनीक आधारित हो। चौथा, लोक नीतियों में ग्रामीण भारत की जनसांख्यिकी व भौगोलिक क्षमता के उपयोग पर बल दिया जाए। पांचवां, ग्रामीण भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति का केंद्र बने।

सतत विकास लक्ष्य की दिशा में ग्रामीण भारत

2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया। 193 देशों ने 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की ओर कदम बढ़ाने का संकल्प लिया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020–21 के तीसरे संस्करण के अनुसार हमने एसडीजी लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा एक तिहाई पूरी कर ली है। देश के समग्र एसडीजी स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है। 2019 के 60 अंक से बढ़कर यह 2020–21 में 66 अंकों तक पहुंच चुका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार असम ने एसडीजी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2030 की समय–सीमा तय की है। हरियाणा ने विज़न 2030 डॉक्यूमेंट के ज़रिए इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कर्नाटक ने तकनीक आधारित 12 क्षेत्रों में बदलाव का लक्ष्य रखा है। आंध्रप्रदेश ने विज़न 2029 की शुरुआत की है।

भारत की लगभग दो तिहाई आबादी गांवों में रहती है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायतों की अग्रणी भूमिका होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर 9 लक्ष्य तय किए हैं। गरीबी से मुक्त गांव, उन्नत आजीविका, स्वास्थ्य, बाल हितैशी, जल संपन्न गांव, स्वच्छता एवं हरियाली, आत्मनिर्भर अधोसंरचना, सामाजिक रूप से सक्षम गांव, सुशासन, महिला सशक्तीकरण इनमें प्रमुख हैं। इन लक्ष्यों को अर्जित करने में केंद्र और राज्यों की एजेंसियों के साथ जनभागीदारी की अहम भूमिका होगी। आज 31 लाख 65 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधि गांव में सुशासन के स्वप्न को साकार कर रहे हैं।

भारत की रणनीति सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण कर सभी हितधारकों को एकीकृत करने की है। जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के लिए भारत स्थानीयकरण पर ज़ोर दे रहा है। हमें अपने गांव का विकास सामर्थ्य के साथ स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी विद अफोर्डेबिलेटी) के सूक्ति वाक्य को ध्यान में रखकर करना होगा। साल 2070 तक नेट ज़ीरो का जो लक्ष्य भारत ने रखा है उसमें ज़ीरो बजट खेती, गांव में अक्षय ऊर्जा का विकास महत्वपूर्ण कारक होगा।

कृषि लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने में नैनो यूरिया जैसे उत्पाद प्रमुख नवाचार हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) द्वारा विकसित 500 मि.ली. की नैनो यूरिया बोतल एक बैग यूरिया के बराबर है। क्षेत्र परीक्षण के अनुसार नैनो यूरिया से किसानों की आय में 2 हजार रुपये प्रति एकड़ की

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास के 17 लक्ष्यों की ओर भारत के बढ़ते कदम

गरीबी उन्मूलन, भूखमरी से मुक्ति, बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तायुक्त शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी व सफाई, अक्षय ऊर्जा, सम्मानजनक आजीविका व आर्थिक विकास, उद्योग–नवाचार एवं अवसंरचना, असमानता को कम करना, टिकाऊ शहर व समुदाय, ज़िम्मेदार उपभोग व उत्पादन, जलवायु समाधान, जल पारिस्थितिकी तंत्र; भूमि की सक्षमता, शांति, न्याय, मज़बूत संस्थान; सतत विकास लक्ष्यों के लिए सहयोग।

औसत वृद्धि दर्ज की जा रही है। नैनो यूरिया तरल सस्ता, अधिक प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल, आसान परिवहन व भंडारण क्षमता वाला उत्पाद है। मिट्टी की उर्वराशक्ति बढ़ाने के लिए देश में 12 करोड़ भूमि स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं।

केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के 91 जलाशयों में 20 प्रतिशत पानी ही बचा है। जलवायु परिवर्तन से यह समस्या और गंभीर हुई है। भू–जल स्तर में गिरावट कुछ इस कदर जारी है कि भूमिगत जल हर साल औसतन एक फीट की दर से नीचे जा रहा है। देश के कई हिस्सों में गांवों में पानी समितियों के गठन के अभूतपूर्व परिणाम सामने आ रहे हैं। इन जल समितियों में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि महिलाओं को जल संरक्षण अभियान का नेतृत्व प्रदान किया जाए तो उसका प्रबंधन प्रभावी होगा। किसानों की आर्थिक स्थिति तभी सुधरेगी जब पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। सूक्ष्म सिंचाई तकनीक इसमें काफी सहायक है। भारत उन 70 देशों में से एक है, जो मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी)* में शामिल है। इस क्रम में देश ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता और 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि की बहाली के लिए कदम बढ़ाया है।

ग्राम्य संस्कृति व अर्थतंत्र के संवाहक मेले व हाट

हमारी सांस्कृतिक चेतना में ग्रामीण भारत का गौरवशाली अतीत रचा–बसा है। ग्रामीण जनजीवन में मेले, उत्सव, लोक कलाओं की विशेष महत्ता है। गांव में लगने वाले मेले ग्रामीण अर्थतंत्र का केंद्र होने के साथ प्राचीन संस्कृतियों के संवाहक हैं। मेलों की पृष्ठभूमि सामान्यतः सामाजिक, आध्यात्मिक, त्योहार, ऋतु परिवर्तन एवं पशुधन पर केंद्रित होती है। यह मेले सामान्यतः पवित्र धार्मिक स्थलों तथा ऐतिहासिक स्थलों पर आयोजित किए जाते हैं। ग्रामीण मेलों व हाट बाज़ार में वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों को नई ऊंचाई देने की क्षमता है। यह स्थानीय उत्पादों जैसे कपड़े, जूते, हस्तशिल्प, इकोफ्रेंडली बर्तन, खिलौनों, खाद्य सामग्री की बिक्री के बड़े केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यह आह्वान समीचीन है जिसमें वह कहते हैं कि यदि अगले 25 साल तक लोग स्थानीय उत्पादों की खरीद करें तो बेरोज़गारी की समस्या खत्म हो जाएगी। यहां होने वाली मनोरंजक गतिविधियां, लोकरंग ग्राम्य जीवन में खुशहाली का वह रंग घोलते हैं, जो उपभोक्तावादी संस्कृति में कहीं पीछे छूट रहा है। देश का ऐसा कोई भी गांव नहीं है, जिसके आसपास कोई स्थानीय मेला न लगता हो। सैकड़ों साल से जारी सूरजकुंड मेला (हरियाणा), पुष्कर मेला (राजस्थान),चेती मेला (काशीपुर, उत्तराखंड), हरेला मेला (भीमताल, उत्तराखंड), सोनपुर मेला (सोनपुर, बिहार), झिड़ी मेला (जम्मू) भगोरिया पर्व (झाबुआ, मध्यप्रदेश) की पहचान विश्व भर में है। इनमें से कई पशुधन व सामग्री विशेष के लिए विश्व व्यापार का केंद्र बन चुके हैं। अकेले राजस्थान में 250 से अधिक पशु मेलों का प्रतिवर्ष आयोजन होता है।

मेलों में छिपी संभावनाओं को अवसर में बदलने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा सरस मेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरस आजीविका मेलों में ग्रामीण भारत की शिल्पकलाएं मुख्य रूप से प्रदर्शित की जाती हैं। यहां स्वयंसहायता समूह की महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बड़ा मंच मिलता है। मेले, साप्ताहिक हाट बाज़ार और स्थानीय उत्सवों में सांस्कृतिक कार्यक्रम व विविध व्यंजन सामाजिक संपर्क का माध्यम बनते हैं। भारत@2047 के फलक को सार्वभौमिक बनाने में ग्राम केंद्रित आर्थिक उपक्रमों के साथ ही स्थानीय लोक कलाओं, संस्कृति और साहित्य को भी सींचना होगा।

*United Nations convention to combat Desertification

संदर्भ

https://amritmahotsav.nic.in
https://www.nabard.org
https://www.google.co.in/books/edition/Gram_Swarajya
https://sdgs.un.org
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1798552
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1760313
https://pmmodiyojana.in
https://www.youtube.com/watch?v=rTISMfbSrbk
https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-02/Annual_Report_2021_2022

(लेखक संचार विशेषज्ञ हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेलः **arvindmbj@gmail.com**